

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए 'सिलीसेड इील मॉडल'
2.	'पीएम-सेतु योजना' के क्रियान्वयन में राजस्थान प्रथम स्थान पर
3.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. विश्व का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेस सेंटर : जयपुर 2. 11वाँ मारवाड़ हॉर्स शो : जोधपुर 3. एक्सरसाइज रुद्र शक्ति - 2026 4. सौर भौतिकी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन - उदयपुर 5. अरुंधति चौधरी - बॉस्को कप में स्वर्ण पदक 6. IIT जोधपुर और SLIET लोंगोवाल के मध्य MoU 7. गायक शहजाद अली : यूथ आइकॉन अवार्ड 8. राजस्थान में 'ईट राइट स्कूल कार्यक्रम' 9. वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल - 2026 10. चर्चा में कानोता, चंदलाई और नेवटा बाँध 11. देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का लेक्रोज (Lacrosse) ग्राउण्ड
4.	बस्तर पंडुम महोत्सव
5.	लोकसभा अध्यक्ष का निलंबन: संवैधानिक प्रक्रिया और अनुच्छेद
6.	बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976: कानून के 50 वर्ष
7.	भारत और सेशेल्स: संयुक्त विज्ञान की घोषणा
8.	विकसित भारत और नेट जीरो: नीति आयोग रिपोर्ट्स



राजस्थान परिदृश्य



आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए 'सिलीसेढ़ झील मॉडल'



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान आर्द्रभूमि प्राधिकरण की नॉलेज पार्टनर संस्था WWF इंडिया द्वारा सिलीसेढ़ झील (अलवर) के लिए ड्राफ्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- ज्ञातव्य है कि अलवर जिले में स्थित सिलीसेढ़ झील को दिसंबर, 2025 में राजस्थान के 5वें और भारत के 96वें रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था।
- WWF इंडिया द्वारा तैयार इस प्लान के तहत सिलीसेढ़ झील को आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। जिसके बाद राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा राजस्थान के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से कम से कम एक आर्द्रभूमि विकसित की जाएगी।
- WWF इंडिया के प्लान में झील की भौगोलिक स्थिति, जलग्रहण क्षेत्र, जल प्रवाह व्यवस्था, जल गुणवत्ता, जलवायु आँकड़े, आर्द्रभूमि स्वास्थ्य, जैव विविधता तथा भविष्य की कार्ययोजना का विस्तृत ब्यौरा प्रदान किया गया है।

सिलीसेढ़ झील के बारे में :

- **अवस्थिति** : अरावली पर्वत श्रृंखला में सरिस्का टाइगर रिज़र्व के बफर क्षेत्र में स्थित। यह झील इस क्षेत्र की जल सुरक्षा, जैव विविधता और स्थानीय आजीविका के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- **निर्माण** : वर्ष 1845 में अलवर महाराजा विनय सिंह द्वारा रूपारेल नदी की सहायक नदी पर एक बाँध बनाकर।
- **अन्य नाम** : राजस्थान का नंदन-कानन।

'पीएम-सेतु योजना' के क्रियान्वयन में राजस्थान प्रथम स्थान पर



चर्चा में क्यों?

- फरवरी, 2026 तक के आँकड़ों के अनुसार पीएम-सेतु योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।



कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT
& ENTREPRENEURSHIP
GOVERNMENT OF INDIA



PM SETU

PRADHAN MANTRI SKILLING AND EMPLOYABILITY TRANSFORMATION THROUGH UPGRADED ITIs



मुख्य बिन्दु:

- राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय के डैशबोर्ड पर योजना से संबंधित सभी 'ग्रीन इंडिकेटर्स' (Green Indicators) हासिल किए।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) को आधुनिक और उद्योग-अनुकूल संस्थानों में बदलना है। इसी संदर्भ में राजस्थान सरकार द्वारा 7 फरवरी, 2026 को 10 वर्ष की अनुबंध अवधि, न्यूनतम पूंजीगत निवेश और परिणाम आधारित प्रशिक्षण जैसे प्रावधान लागू करने हेतु निविदा जारी की गई।

--:4:--

Daily Current Affairs

Date : 11 February, 2026



- पीएम-सेतु योजना के प्रथम चरण में भरतपुर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) को हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- साथ ही, ITI धौलपुर, ITI करौली, ITI कामां और ITI बयाना को स्पोक संस्थानों के रूप में उन्नत किया जाना प्रस्तावित है।
- ज्ञातव्य है कि राजस्थान सरकार द्वारा पीएम-सेतु योजना के पायलट चरण के अंतर्गत दो प्रस्तावित उद्योग क्लस्टरों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। क्लस्टर 1 में भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, करौली, कामां (डीग) और बयाना को शामिल किया गया है।
- पीएम-सेतु योजना के तहत प्रत्येक हब से औसतन चार स्पोक संस्थान जुड़े होंगे, जो अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक मशीनरी, डिजिटल लर्निंग सिस्टम और उन्नत ट्रेड्स से सुसज्जित होंगे।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

पीएम-सेतु योजना:

- **लॉन्च** : 4 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन से।
- **पूरा नाम** : प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs
- **वित्तीय परिव्यय** : ₹60,000 करोड़।
- **प्रकार** : केंद्र प्रायोजित योजना।
- **उद्देश्य** : इस योजना के अंतर्गत देश भर के 1,000 सरकारी ITIs संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिन्हें 200 हब और 800 स्पोक मॉडल में संगठित किया जाएगा।
- **सम्बद्ध मंत्रालय** : कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय।

योजना के घटक:

- **घटक I** - हब और स्पोक मॉडल में 1,000 सरकारी ITIs (200 हब ITIs और 800 स्पोक ITIs) का उन्नयन जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएँ, डिजिटल सामग्री और उद्योग क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप नए पाठ्यक्रम शामिल हैं।

--5--

Daily Current Affairs

Date : 11 February, 2026



- **घटक II** - भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में स्थित NSTI की क्षमता वृद्धि, जिसमें वैश्विक भागीदारी के साथ प्रशिक्षकों के उन्नत प्रशिक्षण पर ध्यान देने के साथ कौशल के लिए क्षेत्र-विशिष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना शामिल है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- **राजस्थान कौशल विकास नीति-2025** : 9 मार्च, 2025 को राजस्थान मंत्रिमंडल ने राज्य में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान कौशल विकास नीति-2025 को मंजूरी दी।
- **राजस्थान रोजगार नीति-2026** : राज्य स्तरीय युवा महोत्सव (12 जनवरी, 2026) के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर में 'राजस्थान रोजगार नीति-2026' जारी की गई। इस नीति के तहत रोजगार और उद्यमशीलता पर केंद्रित बहुआयामी रणनीति के माध्यम से मार्च, 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसरों को सुलभ बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना:

- **शुभारंभ** : 12 जनवरी, 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा।
- इस योजना के तहत 1 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देकर सूक्ष्म उद्यमी के रूप में तैयार किया जाएगा।
- **पात्रता** : राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए और आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

--6--

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>विश्व का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर : जयपुर</p> <ul style="list-style-type: none">मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव ने 09 फरवरी, 2026 को जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (NIA) के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान संस्थान परिसर में विश्व के पहले आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया।साथ ही, औषधीय पौधों के उद्यान धन्वंतरि उपवन का भी उद्घाटन किया गया।इस एक्सीलेंस सेंटर में औषधीय पौधों की DNA बारकोडिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग और गुणवत्ता परीक्षण से डेटा बैंक तैयार किया जाएगा।
2.	<p>11वाँ मारवाड़ हॉर्स शो : जोधपुर</p> <ul style="list-style-type: none">आयोजन : महाराजा गजसिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन (MGSF) पोलो ग्राउंड (पाबूपुरा), जोधपुर।आयोजक : 'ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी' और 'मारवाड़ी हॉर्स बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया'।अवधि : 7 और 8 फरवरी, 2026।मुख्य उद्देश्य : मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों का संरक्षण करना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना।
3.	<p>एक्सरसाइज रुद्र शक्ति - 2026</p> <ul style="list-style-type: none">आयोजन स्थल : पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर।आयोजक : रुद्र ब्रिगेड (सदर्न कमांड, पुणे)।'एक्सरसाइज रुद्र शक्ति 2026' एक 'ऑल-आर्म्स' (सभी सैन्य अंगों का संयुक्त) युद्धाभ्यास था, जिसका मुख्य उद्देश्य भविष्य के युद्धों के लिए आधुनिक तकनीकों का परीक्षण करना था।यह युद्धाभ्यास 'एक्सरसाइज अखंड प्रहार' की अगली कड़ी के रूप में आयोजित किया गया।

4.	<p>सौर भौतिकी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन - उदयपुर</p> <ul style="list-style-type: none">■ उदयपुर सौर वेधशाला (USO) की स्वर्ण जयंती के अवसर पर सौर भौतिकी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।■ थीम : 'एक्सप्लोरिंग द सन एट हाई-रिजोल्यूशन: प्रेजेंट पर्सपेक्टिव्स एंड फ्यूचर होराइजन्स'।■ आयोजन अवधि : 10 से 13 फरवरी, 2026 तक।
5.	<p>अरुंधति चौधरी - बॉस्को कप में स्वर्ण पदक</p> <ul style="list-style-type: none">■ कोटा निवासी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने स्पेन के एलिकैंट में आयोजित बॉस्को कप इन्टरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।■ अरुंधति चौधरी ने फाइनल में यूक्रेन की बॉक्सर तरन अनस्टेशिया को 5-0 से हराया।■ इस प्रतियोगिता का आयोजन 2 से 7 फरवरी, 2026 तक किया गया।■ इससे पहले 4 से 10 जनवरी, 2026 तक ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में आयोजित 9वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता था।
6.	<p>IIT जोधपुर और SLIET लोंगोवाल के मध्य MoU</p> <ul style="list-style-type: none">■ हाल ही में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, जोधपुर ने एकेडमिक सहयोग को मज़बूत करने, रिसर्च में सहयोग को बढ़ावा देने और स्टूडेंट्स के लिए एडवांस्ड रिसर्च के लिए संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (SLIET), लोंगोवाल के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया।■ यह एग्रीमेंट IIT जोधपुर और SLIET लोंगोवाल के बीच एकेडमिक एक्सीलेंस और रिसर्च इनोवेशन में सहयोग को बढ़ावा देगा।
7.	<p>गायक शहजाद अली : यूथ आइकॉन अवार्ड</p> <ul style="list-style-type: none">■ बीकानेर निवासी गायक शहजाद अली को हाल ही में आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (RIFF) - 2026 में 'यूथ आइकॉन अवार्ड' से सम्मानित किया गया।■ उन्हें यह पुरस्कार राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (RIFF) के 12वें संस्करण के दौरान मेहरानगढ़ किले में दिया गया।

8.	<p>राजस्थान में 'ईट राइट स्कूल कार्यक्रम'</p> <ul style="list-style-type: none">■ राजस्थान में ईट राइट स्कूल कार्यक्रम का संचालन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मार्गदर्शन में राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय) द्वारा किया जा रहा है।■ मुख्य उद्देश्य : स्कूली बच्चों में खाद्य सुरक्षा, पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना है, ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित खान-पान की आदतें विकसित कर सकें।■ यह पहल राज्य सरकार के 'निरामय राजस्थान' अभियान के अंतर्गत संचालित की जा रही है, जिसका लक्ष्य प्रदेश के लगभग 10,000 स्कूलों को कवर करना है।■ स्कूलों का मूल्यांकन और प्रमाणीकरण FSSAI द्वारा विकसित 'ईट राइट मैट्रिक्स' के आधार पर किया जाता है।
9.	<p>वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल - 2026</p> <ul style="list-style-type: none">■ आयोजन : 6 से 8 फरवरी, 2026 तक पिछोला झील, उदयपुर।■ थीम : 'म्यूजिक विदाउट बॉर्डर्स'।■ संस्करण: 10वाँ।■ आयोजक: 'सहर' (Seher), राजस्थान पर्यटन विभाग और हिन्दुस्तान जिंक।
10.	<p>चर्चा में कानोता, चंदलाई और नेवटा बाँध</p> <ul style="list-style-type: none">■ राजस्थान सरकार कानोता, चंदलाई और नेवटा बाँध को प्रदूषण मुक्त करने और इन्हें इको-टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए एक विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करा रही है।■ ये तीनों बाँध जयपुर जिले में स्थित है।
11.	<p>देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का लेक्रोज (Lacrosse) ग्राउण्ड</p> <ul style="list-style-type: none">■ देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का लेक्रोज (Lacrosse) ग्राउण्ड उदयपुर के महाराणा प्रताप खेलगांव में निर्मित किया गया है।■ उदयपुर में ही प्रदेश की पहली लेक्रोज एकेडमी भी स्थापित की गई है।



राष्ट्रीय परिदृश्य



बस्तर पंडुम महोत्सव



चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को 'बस्तर पंडुम' त्योहार के आयोजन के लिए बधाई दी।



मुख्य बिन्दु:

महोत्सव के बारे में

- बस्तर पंडुम छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है, जो आदिवासी विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करता है।
- 7 से 9 फरवरी तक आयोजित होने वाला यह महोत्सव कला, संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प और स्वदेशी व्यंजनों के माध्यम से बस्तर की आदिवासी पहचान को उजागर करने वाले एक प्रमुख सांस्कृतिक मंच के रूप में उभरा है।

--:10:--

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

लोकसभा अध्यक्ष का निलंबन: संवैधानिक प्रक्रिया और अनुच्छेद

चर्चा में क्यों?

- विपक्षी दल (INDIA गठबंधन) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव / निलंबन प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, उनका आरोप है कि उन्होंने पक्षपाती आचरण किया है, सांसदों को बोलने का अवसर नहीं दिया, सांसदों को निलंबित किया, और कुछ सदस्यों के खिलाफ शिकायतों की अनदेखी की।

मुख्य बिन्दु:

संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद

- अनुच्छेद 93:** लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सदन द्वारा किया जाता है।
- अनुच्छेद 94:** इसके तहत निम्नलिखित प्रावधान हैं:
 - पद का त्याग
 - इस्तीफा
 - लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके निलंबन (लोकसभा के कुल सदस्यता का बहुमत आवश्यक)
 - प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले 14 दिन का नोटिस अनिवार्य है।

अध्यक्ष के निलंबन की प्रक्रिया

- लिखित नोटिस (कम से कम 14 दिन पहले) महासचिव को प्रस्तुत किया जाता है।
- प्रस्ताव को चर्चा और मतदान के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।
- यह प्रस्ताव लोकसभा के कुल सदस्यता के बहुमत से पारित होना चाहिए।
- इस प्रक्रिया के दौरान उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य सदन की अध्यक्षता करते हैं।
- जब निलंबन प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो, अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं करेंगे।

--:11:--

विवाद के कारण

- सत्ताधारी पार्टी को लाभ पहुंचाने का आरोप
- राष्ट्रीय हित से ऊपर पार्टी हित
- विधेयक समितियों को नहीं भेजे जाते
- कभी-कभी विधेयकों को उच्च सदन से पारित कराने के लिए 'धन विधेयक' का लेबल दे दिया जाता है। उदाहरणार्थ चुनावी बांड को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया।
- 10वीं अनुसूची के तहत शक्तियों का दुरुपयोग
- आम तौर पर स्पीकर का चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी से होता है, जिससे पार्टी के प्रभाव से उनकी स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं।

संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु (1992)

- सुप्रीम कोर्ट ने पक्षपातपूर्ण घटनाओं का हवाला देते हुए संसद को स्पीकर की शक्तियों पर पुनर्विचार करने पर विचार करने को कहा है।
- इसने अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र न्यायाधिकरणों का सुझाव दिया है।

नबाम रेबिया बनाम बेमांग फेलिक्स मामले (2016)

- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि किसी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित है, तो उसके लिए अयोग्यता कार्यवाही को आगे बढ़ाना "संवैधानिक रूप से अनुचित" है।

कैशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर (2020)

- सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों को संभालने के लिए न्यायाधीशों के नेतृत्व में एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण बनाने हेतु संविधान में संशोधन करने की सिफारिश की।

With reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements :

While any resolution for the **removal of the Speaker** of the Lok Sabha is under consideration

1. He/She shall not preside.
2. He/She shall not have the right to speak.
3. He/She shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance.

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 1 and 2 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

समाजशास्त्र

बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976: कानून के 50 वर्ष

चर्चा में क्यों?

- 9 फरवरी, 1976 को बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम के लागू होने के साथ भारत में समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित हुआ।



मुख्य बिन्दु:

अतिरिक्त जानकारी

- बंधुआ मजदूरी को ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ पैसा इस तरह से उधार दिया जाता है कि देनदार को पैसे के बजाय श्रम के माध्यम से चुकाने के लिए मजबूर किया जाता है।
- बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, को संविधान के अनुच्छेद 23 (मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध) को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया।
- गरीबी, जातिगत भेदभाव, भूमिहीनता और कर्ज के कारण बंधुआ मजदूरी की प्रथा गहराई से जड़ें जमा चुकी थी।
- भारत ने 1954 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) कन्वेंशन संख्या 29 (जबरन श्रम) की पुष्टि की, जिससे कानूनी दायित्व मजबूत हुआ।

--:14:--

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

भारत और सेशेल्स: संयुक्त विज्ञान की घोषणा

चर्चा में क्यों?

- राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सेशेल्स के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए।

मुख्य बिन्दु:

- भारत और सेशेल्स ने उन्नत संपर्कों के माध्यम से 'सतत विकास, आर्थिक संवृद्धि और सुरक्षा' के लिए एक संयुक्त विज्ञान की घोषणा की।



प्रमुख परिणाम

- **विशेष आर्थिक पैकेज:** भारत ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण और समुद्री सुरक्षा के लिए कुल 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की घोषणा की।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** सेशेल्स कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) का पूर्ण सदस्य बनेगा।
- CSC एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है। इसमें भारत, श्रीलंका, मॉरीशस, मालदीव और बांग्लादेश शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य सदस्य देशों की साझा चुनौतियों और खतरों से निपटकर क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
- **आपदा प्रतिरोधकता:** सेशेल्स 'आपदा-रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन' (CDRI) में शामिल होने के लिए सहमत हुआ।
- **स्वास्थ्य:** सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं खरीदने के लिए सेशेल्स 'इंडियन फार्माकोपिया' (दवाओं के मानकों की पुस्तक) को मान्यता देगा।
- **डिजिटल परिवर्तन:** भारत सेशेल्स में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) बनाने के लिए व्यापक प्रयास करने पर सहमत हुआ।
- **समुद्री सहयोग:** सेशेल्स भारतीय सहायता से एक हाइड्रोग्राफिक यूनिट (जल सर्वेक्षण इकाई) स्थापित करेगा।

भारत के लिए सेशेल्स का महत्व

- **महासागर व सागर विज्ञान:** सेशेल्स भारत के सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) तथा हाल ही में घोषित 'विज्ञान महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) का एक केंद्रीय स्तंभ है।
- **भू-सामरिक:** महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों के निकट इसकी स्थिति प्रमुख पोत परिवहन मार्गों (जैसे- मोजाम्बिक चैनल) की निगरानी में मदद करती है।
- **उदाहरण:** निगरानी बढ़ाने के लिए 'अजम्पशन द्वीप' को विकसित करने का भारत का प्रयास।
- **चीन के विस्तार को संतुलित करना:** भारत ने सेशेल्स में 'तटीय निगरानी रडार प्रणाली' की तैनाती की है।
- **UNSC उम्मीदवारी:** सेशेल्स संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है।
- **रक्षा सहयोग:** उदाहरण- संयुक्त समुद्री अभ्यास 'लामित्ये' (LAMITYE) का आयोजन।

--:16:--

महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट

विकसित भारत और नेट जीरो: नीति आयोग रिपोर्ट्स

चर्चा में क्यों?

- नीति आयोग ने विकसित भारत और नेट जीरो की दिशा में परिदृश्यों पर तीन अध्ययन रिपोर्ट जारी की हैं।



मुख्य बिन्दु:

- ये रिपोर्ट्स एक समग्र रोडमैप, व्यापक आर्थिक निहितार्थ और वित्त-पोषण की आवश्यकताओं पर केंद्रित हैं।
- विकसित भारत 2047:** इसका लक्ष्य भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र और 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।

Daily Current Affairs

Date : 11 February, 2026



- **नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य:** भारत ने 2070 तक नेट जीरो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता प्रकट की है।

प्रमुख आर्थिक निहितार्थ

जीडीपी पर कम प्रभाव और उच्च निवेश की आवश्यकता

- **निवेश-आधारित संवृद्धि की ओर बढ़ना:** नेट जीरो लक्ष्य के अनुसरण में अर्थव्यवस्था संरचनात्मक रूप से 'उपभोग-आधारित' संवृद्धि से 'पूंजी-प्रधान' संवृद्धि की ओर पुनर्संतुलित होगी।
- **औद्योगिक विस्तार:** स्वच्छ ऊर्जा और विनिर्माण के कारण 2050 तक औद्योगिक GVA (सकल मूल्य वर्धित) बढ़कर लगभग 33% होने का अनुमान है।
- जीवाश्म ईंधन आधारित विनिर्माण में कमी आने का अनुमान है।
- **रोजगार पुनरावंटन:** नौकरियाँ जीवाश्म ईंधन क्षेत्रों से हटकर नवीकरणीय ऊर्जा, निर्माण, परिवहन और स्वच्छ विनिर्माण की ओर बढ़ेंगी।
- **आयात निर्भरता में कमी:** ईंधन आयात बिल जो वर्तमान में जीडीपी का 4% है, उसके 2070 तक घटकर 0.2% होने का अनुमान है।

--:18:--